जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 51 संख्याः 60 प्रभात कोटा, शनिवार 13 दिसम्बर, 2025 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

रूपए की लुढ़कती कीमत ने भारत-अमेरिका ''ट्रेड'' समझौते को और जटिल बनाया

अमेरिका को एक और तर्क मिल गया, ''टैरिफ'' नहीं घटाने के लिए, या कितना टैरिफ घटाना है, उसकी सौदेबाजी के लिए

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर। पिछले एक हफ्ते में भारतीय रुपये के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुँचने, यू.एस. डॉलर के मुकाबले 90 के पार जाने और एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा के तौर पर अपनी जगह पक्की करने से आर्थिक नतीजों की एक लहर शुरु हो गई है, जिसे भारत को सावधानी से मैनेज करना होगा। यह स्थिति ऐसे समय बनी है, जब भारत अमेरिका के साथ एक लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहा है, और रुपये की अस्थिरता अर्थव्यवस्था की गहरी कमजोरियों को उजागर कर रही है।

- तर्क यह है कि रूपए का मूल्य घटने से भारत को निर्यात में माल सस्ता होने का ''एडवांटेज'' मिलेगा।
- पर, रूपए का मूल्य घटने से, भारत का ''ऑयल इंपोर्ट'' बिल, जो डॉलर में ही होता है, और बढ़ता जाएगा। ''ट्रांसपोर्टेशन'' महंगा होने से देश में हर वस्तु के दाम प्रभावित होंगे। साग-सब्जी से कंस्ट्रक्शन मटीरियल तक सब कुछ महंगा होगा तथा हर व्यक्ति का घर खर्च बढ़ेगा।
- विदेश में बच्चों को पढ़ाना, इलाज कराना, विदेशी दवाइयां व उपकरण महंगे हो जाएंगे।
- भारतीय उद्योगपतियों व व्यापारियों में इन दिनों होड़ लगी थी, विदेशी वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए। यह ऋण और इस ऋण की अदायगी महंगी हो जाएगी।

मुद्रा का यह झटका वॉशिंगटन के साथ भारत की व्यापार वार्ताओं में एक नया पहलू जोड़ता है। कमजोर रुपया भारत को थोड़े समय के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देता है, लेकिन यह जांच को भी बुलावा देता है। अमेरिकी वार्ताकार तर्क दे सकते हैं कि एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव भारत को पहले ही फायदा दे रहा है, और इससे टैरिफ में कमी पर बातचीत और कठिन हो सकती है।

इस स्थिति की जड़ में है, भारत की आयात पर भारी निर्भरता। कमजोर रुपया कच्चे तेल को तुरंत महंगा कर देता है, जो भारत की खपत का लगभग 85 प्रतिशत है और देश के परिवहन, उत्पादन और ऊर्जा क्षेत्रों की सबसे बड़ी जरूरत है। अब तेल का हर डॉलर, रुपए के हिसाब से काफी महंगा हो गया है, जिससे तेल कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है और सरकार को ईंधन की कीमतों पर कठिन फैसले लेने पड़ रहे हैं। महंगा ईंधन अर्थव्यवस्था पर तेजी से असर डालता है, माल ढुलाई बढ़ती है और सब चीजें, सब्जियों और निर्माण सामग्री से लेकर उपभोक्ता वस्तुओं तक, और महंगी हो जाती हैं। यह आयातित महंगाई सीधे घरों के खर्चों पर चोट करती है, खासकर निम्न और मध्यम वर्ग के बजट पर।

विदेश में पढ़ाई, विदेश यात्राएँ, चिकित्सा प्रक्रियाएँ और यहाँ तक कि, आयातित दवाएँ और उपकरण भी काफी महंगे हो गए हैं। जिन परिवारों के बच्चे अमेरिका या यूरोप में पढ़ रहे हैं, उनके मासिक खर्च बढ़ गए हैं क्योंकि ट्यूशन, रहने और रोज़मर्रा का खर्च अब महंगे डॉलर में देना पड़ रहा है। रुपये की गिरावट ने कंपनियों की बैलेंस शीट भी मुश्किल में डाल दी है। जिन कंपनियों पर डॉलर में कर्ज है, उनके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पूर्व केन्द्रीय मंत्री और स्पीकर शिवराज पाटिल का निधन

लातूर/नयी दिल्ली, 12 दिसंबर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज विश्वनाथ पाटिल का शुक्रवार सुबह महाराष्ट्र के लातूर में निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे। पाटिल पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे।

उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने दुख प्रकट किया है। पाटिल ने लंबे समय तक कई संवैधानिक पदों पर कार्य किया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और पंजाब के राज्यपाल सहित कई प्रमुख पदों पर कार्य किया था। पाटिल को एक प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञ और संवैधानिक मामलों के जानकार के रूप में जाना जाता था।

- राष्ट्रपति मुर्मू, प्र.मंत्री मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्रियों व नेताओं ने शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि दी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यूपी का नया प्रदेशाध्यक्ष बनाने के लिए ताबड़-तोड़ तरीके से लगी भाजपा

भाजपा 16 दिसंबर से पहले, खर मास प्रारंभ होने से पहले, इस नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर देना चाहती है

- श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 दिसंबर। बिहार चुनाव खत्म होने के बाद, भाजपा ने लंबे समय से लंबित नये अध्यक्ष के चुनाव के मुद्दे को हल करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस दिशा में शुक्रवार को एक बड़ा संकेत तब मिला, जब पार्टी ने उत्तर प्रदेश में नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की, जहां विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं।

भाजपा के संविधान के अनुसार, राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष तब चुना जा सकता है, जब आधे राज्यों की संगठनात्मक इकाइयों के प्रमुखों का चुनाव हो चुका हो। हालांकि यह शर्त तीन महीने पहले पूरी हो चुकी थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा शेष था। उत्तर प्रदेश, जहाँ कुल 80 लोकसभा सीटें है, में नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुना गया था।

- वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद तावड़े, शनिवार को लखनऊ जा रहे हैं और अगर एक ही नाम प्रस्तावित हुआ तो चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल रविवार को नये अध्यक्ष की घोषणा कर देंगे।
- यह तो पूर्व निश्चित है कि नया प्रदेशाध्यक्ष एक ओबीसी नेता ही होगा। क्योंकि गत लोकसभा चुनाव में गैर यादव ओबीसी भाजपा का साथ छोड़कर सपा के समर्थन में कूद गए थे जिससे भाजपा को भारी नुकसान हुआ था।
- पंकज चौधरी, जो मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं, इस प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे हैं। पंकज कुर्मी हैं तथा मु.मंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले के ही रहने वाले हैं।
- अन्य दो ओबीसी नेता, धर्मपाल सिंह (लोध) तथा साध्वी निरंजना ज्योति (निषाद) भी अभी इस दौड़ में प्रतिद्वंदी हैं।

कल से गतिविधियों की हलचल शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी गुरुवार को दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद तावड़े शनिवार को लखनऊ जाएंगे, ताकि नए राज्य पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया की निगरानी कर सकें। यदि केवल एक नामांकन होता है, तो नए अध्यक्ष का नाम रविवार को ही राज्य चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन यदि दो या दो से अधिक नामांकन होते हैं, तो चुनाव होंगे। किसी भी स्थिति में, नए राज्य पार्टी अध्यक्ष की घोषणा 16 दिसंबर से पहले हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद हिंदू कैलेंडर का मलमास शुरु हो जाएगा।

भाजपा के संगठनात्मक चुनाव

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी ने बिहार जीत की खुशी में एनडीए सांसदों को लाजवाब भोज दिया

रात्रिभोज में भारत के विभिन्न प्रांतों के लजीज़ शाकाहारी व्यंजन परोसे गए

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11 दिसंबर को नई दिल्ली में अपने आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग पर सत्तारूढ़ नैशनल डैमोक्रेटिक एलायंस (एनडीए) के सांसदों के लिए एक शानदार रात्रिभोज का आयोजन किया। यह भोज बिहार विधानसभा चुनावों में हाल ही में मिली विशाल सफलता के बाद आयोजित किया गया था।

- केन्द्रीय मंत्री ने 11 दिसंबर की रात दिए गए रात्रिभोज का वीडियो एक्स पर शेयर किया और रात्रिभोज के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया।
- एनडीए के सभी सांसदों को बस में बिठाकर प्रधानमंत्री आवास, 7, लोक कल्याण मार्ग ले जाया गया था।

केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एनडीए सांसद प्रधानमंत्री के आवास पर जाने के लिए बस में सवार हो रहे हैं। रिजिजू ने लिखा कि ''हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आभारी हैं, जिन्होंने एनडीए सांसदों के लिए 7 लोक कल्याण मार्ग पर रात्रिभोज का आयोजन किया। पूरे कार्यक्रम का माहौल बेहद पारिवारिक था।''

मेहमानों का स्वागत ताजगी से भरपूर अदरक वाले संतरे के रस और अनार के रस से किया गया। यह पेय पदार्थ एक शक्तिशाली इम्युनिटी बूस्टर माना जाता है। अदरक का तीखा स्वाद स्वाभाविक रूप से खट्टे मीठे संतरे और मीठे अनार के स्वाद के साथ अद्‌भुत स्वाद पेश कर रहा था।

इसके बाद, मेहमानों को भारतीय व्यंजनों की परम्परा वाले ऐपटाइज़र्स पेश किए गए, जिनमें एक मजेदार ऐपटाइज़र (स्नैक) सब्ज बादाम शोरबा प्रमुख था, जो मौसमी सब्जियों, बादाम और मसालों से बनाया जाता है। ककुम मटर अखरोट की शम्मी भी परोसी गई, बाजरे से बनी और तवे पर सिकी इस डिश में, हरे मटर और कटे हुए अखरोट डाले गए थे, इसके अलावा हरा धनिया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

खेड़ा को 100 करोड़ का मानहानि नोटिस

नई दिल्ली, 12 दिसंबर। कांग्रेस प्रवक्ता और पार्टी के मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा को सोशल मीडिया एक्स पर उनकी एक पोस्ट के लिए 100 करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस भेजा गया है। खेड़ा ने यह पोस्ट शुक्रवार सुबह किया था।

यह कानूनी नोटिस ''द स्टेट्समैन लिमिटेड'' के चेयरमैन और समाचार एजेंसी यूएनआई के निदेशक आर पी गुप्ता की ओर से भेजा गया है। खेड़ा ने अपने विवादास्पद पोस्ट में यह संकेत दिया है कि देश के ''सबसे ऊंचे पद'' पर बैठे किसी व्यक्ति ने गुप्ता को एक

- कांग्रेस प्रवक्ता को यह कानूनी नोटिस उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर स्टेट्समैन लिमिटेड के चेयरमैन व यूएनआई के निदेशक आर.पी. गुप्ता ने भेजा है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'वायु प्रदूषण नैशनल इमरजैंसी है संसद में इस पर सार्थक बहस होनी चाहिए'

राहुल गांधी के इस आग्रह पर केन्द्र सरकार ने सकारात्मक रूख दर्शाया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर। संसदीय लोकतंत्र की वास्तविक सहयोगात्मक भावना को दर्शाते हुए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज संसद से अपील की कि वह आरोप-प्रत्यारोप से परे जाकर, भारत के बिगड़ते वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए मिलकर काम करे और संकीर्ण दलगत राजनीति से ऊपर उठे।

गांधी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब कांग्रेस और सरकार के बीच हालिया विवादों के कारण लोकसभा के अंदर और बाहर काफी राजनीतिक तनाव बना हुआ है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की ओर से यह पहल तथा सरकार की वैसी ही प्रतिक्रिया का अवसर पिछले 10 वर्षों में एक दुर्लभ क्षण था, जब दोनों पक्षों ने साझा उद्देश्य की भावना दिखाई।

- दस साल में पहली बार ऐसा दुर्लभ क्षण आया है संसद में जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किसी मुद्दे पर पूर्ण सहमति देखी गई।
- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा भारत के अधिकांश शहरों में हवा ज़हरीली है, बच्चों व बुजुर्गों का स्वास्थ्य इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, इससे निपटने के लिए हमें लोकसभा में चर्चा करनी चाहिए।
- उन्होंने कहा, ना तो यह पूछें कि अब तक क्या किया और क्या नहीं किया, ना ही हम आप पर आरोप लगाएं और आप हम पर, बस यह बात की जाए कि देश की भावी पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं।
- राहुल के प्रस्ताव पर सरकार ने सकारात्मक रूख दर्शाया और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सरकार पहले दिन से ही प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।

लोकसभा में बोलते हुए गांधी ने कहा कि भारत के अधिकांश बड़े शहर ''जहरीली हवा की चादर के नीचे जी रहे हैं'', और चेतावनी दी कि बच्चे, बुजुर्ग तथा शारीरिक रुप से अन्य संवेदनशील लोग लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से अपने स्वास्थ्य पर गम्भीर असर का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ''लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। उनका भविष्य नष्ट हो रहा है। लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं। बुजुर्गों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है।'' उन्होंने जोर देकर कहा कि वायु प्रदूषण कोई विचारधारा का मुद्दा नहीं है और इसे दलगत आरोप-प्रत्यारोप में नहीं बदलना चाहिए।

उन्होंने चर्चा की रूपरेखा में पूर्ण परिवर्तन का सुझाव दिया और कहा ''मेरा मानना है कि एक अच्छा तरीका यह होगा कि हम चर्चा को इस आधार पर न रखें कि आपने क्या नहीं किया या हमने क्या नहीं किया, बल्कि इस पर रखें कि भविष्य में भारत के लोगों के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हमें कौन से कदम उठाने की जरुरत है।''

उन्होंने कहा, ''इस सदन में हर कोई इस बात से सहमत होगा कि वायु प्रदूषण

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल के खिलाफ मानहानि केस में 23 दिसम्बर को सुनवाई

सुलतानपुर, 12 दिसंबर। उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर जिले की एमपी/एमएलए कोर्ट में शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई टल गई। यह सुनवाई राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला द्वारा समय लेने के कारण स्थगित हुई। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तारीख तय की है।

- सुनवाई शुक्रवार को होनी थी पर राहुल गांधी के वकील ने गवाह से जिरह के लिए समय मांगा इस लिए कोर्ट ने 23 दिसम्बर की तारीख दी है।

कांग्रेस नेता व रायबरेली सांसद राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

1976 में 40 साल तक लोकसभा सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया गया था

2026 में यह अवधि पूरी हो रही है तथा लगभग तभी जनसंख्या की डिजिटल काउंटिंग भी पूरी हो जाएगी तथा इसके बाद लोकसभा सीटों का ''डीलिमिटेशन'' भी होगा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर। भारत पाँच दशकों पोलिटिकल रिप्रैज़ेंटेशन की सबसे बड़ी पुनर्संरचना (रीकैलिबरेशन) की ओर बढ़ रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा आने वाले दो वर्षों में डिजिटल जनगणना पूरी करने के फैसले ने देश में एक जोरदार बहस को दोबारा शुरू कर दिया है।

यह कदम लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के लम्बे समय से लंबित परिसीमन (डीलिमिटेशन) के लिए मंच तैयार करता है, एक ऐसा कदम, जिसके बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि इससे ज्यादा आबादी वाले उत्तरी राज्यों और जनसंख्या के मामले में स्थिर दक्षिणी राज्यों के बीच शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव आएगा।

लोकसभा सीटों का अंतिम बार पुनर्वितरण 1970 के दशक की शुरुआत में हुआ था। उसके बाद 1976 में लगाई गई संवैधानिक रोक, ताकि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को नुकसान न हो, ने जनसंख्या के आधार पर किसी भी बदलाव को रोक दिया। यह रोक 2026 में समाप्त हो रही है, जिससे एक नया राजनीतिक दौर शुरू होता दिखाई दे रहा है।

ऊँचे पदों पर मौजूद सरकारी सूत्रों ने पुष्टि की है कि जैसे ही नई जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध होंगे, ''परिसीमन तुरंत शुरू हो जाएगा।'' इसके प्रभाव बहुत स्पष्ट होंगे। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे उत्तरी राज्य, जहाँ आबादी लगातार बढ़ी है, लोकसभा में अपनी प्रतिनिधित्व संख्या में बड़ा फायदा उठाएंगे।

- दक्षिण भारत के प्रदेशः तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आँध्र व तेलंगाना, इस ''डीलिमिटेशन'' से काफी आशंकित हैं।
- उनका भय है कि अगर ''डीलिमिटेशन'' का आधार केवल जनसंख्या ही हुई तो दक्षिण भारत की लगभग चालीस सीटें कम हो जाएंगी लोकसभा में और उत्तर भारत के राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की लोकसभा सीटों की संख्या में लगभग 60 सीटों की वृद्धि होगी।
- और इसके बाद, उत्तर भारत की विधानसभा में विधायकों की संख्या भी बढ़ जाएगी, जिससे राज्यसभा में भी उत्तर भारत के प्रदेशों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और इसके बाद केन्द्र से राज्यों को आवंटित राशि में भी उत्तर भारत का हिस्सा बढ़ जाएगा।
- जबकि, दक्षिण भारत का योगदान केन्द्रीय सरकार के आर्थिक कोष में उत्तर भारत से ज्यादा है।

अनुमानों के मुताबिक, यदि पूरी तरह जनसंख्या अनुपात के आधार पर परिसीमन किया गया, तो इन राज्यों को 40 से 60 नई लोकसभा सीटें मिल सकती हैं।

इसके बिल्कुल विपरीत, कम प्रजनन दर वाले दक्षिणी राज्य, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 20 से 40 सीटें तक खो सकते हैं। महाराष्ट्र में भी सीटें घटने की संभावना है क्योंकि राष्ट्रीय जनसंख्या में उसकी हिस्सेदारी कम हुई है।

इस संभावित बदलाव से पूरे दक्षिण भारत में बेचैनी फैल गई है। डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि केवल जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करने से दक्षिण भारत ''राजनीतिक रूप

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल की बैठक में नहीं आए थरुर

नई दिल्ली, 12 दिसंबर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई पार्टी की लोकसभा सांसदों की बैठक में शामिल नहीं हुए। थरूर की प्रमुख बैठकों से बार-बार गैरहाजिरी को लेकर पार्टी के अंदर अब सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, शशि थरूर ने बैठक से अपनी अनुपस्थिति को लेकर पहले ही नेतृत्व को जानकारी दे दी थी, लेकिन कांग्रेस के चीफ व्हिप का कहना है कि उन्हें उनकी अनुपस्थिति के कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

- कांग्रेस सांसद शशि थरुर लगातार तीसरी बार कांग्रेस सांसदों की बैठक से अनुपस्थित रहे हैं।

तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं, जिसको लेकर भी उन पर सवाल उठे हैं। अब वो कांग्रेस की औपचारिक बैठकों भी शामिल नहीं हो रहे हैं, ऐसे में सवाल उठने लाजिमी हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)